INDIAN BUSINESS PARTY
इंडियन बिजनेस पार्टी

www.indianbusinessparty.org

प्रधान मंत्री कार्यालय
Prime Minister's Office
डाक अनुभाग
DAK SECTION
Date 14/6/17

आदरणीय प्रधान मंत्री जी

एक जुलाई से देश में GST लागू होने जा रहा है| सरकार उत्साहित है पर कारोबारी वर्ग भयभीत है | भारत में अभी भी कारोबारी इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि पेचीदा कानूनों को ठीक से पड़ सके | यही कारण है की आज भी कारोबारिओ को पग पग पर वकीलों और चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है | भारत की ६० % जनता, जो गांव देहात में रहती है ,के उपभोग की वस्तुओ क़ी पूर्ति स्थानिए छोटा और माध्यम कारोबारी करता है | न तो वह पर बिजली है और नहीं हे इंटरनेट ,कैसे वह E Way बिल बनाएगा और कैसे विवरणी दाखिल करेगा ? इनके अतिरिक्त GST कानून में बहुत सी विसंगतिआ है ,जिनका निदान होना अति आवशयक है |

GST के किसी भी कानून के पालन में यदि छोटे व्यापारिओं से कोई गलती हो जाती है तो, सीधा कोई दंडात्मक कार्यवाही न करके, स्थानीय व्यापर मंडल के माध्यम से उक्त व्यापारी को गलती सुधर का मौका दिया जाना चाहिय | इसी प्रकार किसी भी व्यवसायिक परिसर में GST अधिकारी स्थानीय व्यापार मंडल के प्रतिनिधिओ को अपने साथ लेकर जाय |

GST लागू होने पर कार्यशील पूँजी के आवशयकता लगभग 25 -30 प्रतिशत बाद जाएगी और बड़े हुए ब्याज के कारण व्यवसाय का लाभ ,नुकसान में परिवर्तिति होने का भय है | अतः बैंको को निर्देशित किया जाए के व्यापारिओं की कार्य शील पूंजी में 25 % वृद्धि की जाए और वह ब्याज मुक्त हो क्यूंकि सरकार वस्तुओ के उपभोग से पहले ही GST वसूल कर चुकी होती है |

GST के वर्तमान स्वरुप में लघु उदयमी के समाप्त हो जाने का भय है | अभी तक वह 1 .50 करोड़ रूपए की छूट पता था और अपना माल प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों में बेचता था | अब यह प्रतिस्पर्धा ही समाप्त हो जाएगी क्यूंकि अब कोई छूट उब्लब्ध नहीं है |

छोटे व्यापारिओं को composition स्कीम में भी गैर पंजीकृत व्यापारिओं से माल खरीदने पर Reverse पद्धति में भी टैक्स देना पड़ेगा जो उस पर एक अतिरिक्त वित्तिय बोझ है |

माननीय प्रधान मंत्री जी जिस देश की प्रजा राजाज्ञा से भयभीत हो तो शासन का कर्त्तव्य है कि जनता की सभी शंकाओ का निवारण उचित प्रकार किया जाए | जिस प्रकार नोट बंदी के पश्चात् अर्थव्यवस्था में 2 % के गिरावट दर्ज़ हुई उसी प्रकार GST लागू होने पर अर्थव्यवस्था में गिरावट स्वाभाविक है | देश क़ी सीमाओं पर अशांति है , देश के भीतर किसान भी अशांत हैं ऐसे में यदि GST लागू होने के कारण कारोबार में या अर्थव्यवस्था में गिरावट आई तो देश पर गंभीर आर्थिक संकट आ सकता है | यद्पि कुछ व्यापारी नेता अपने रजनीतिक स्वार्थ के चलते ऊपर से GST का समर्थन तो कर रहे है पर अंदर से वह स्वयं भी भयभीत है |

Pragati Tower, 26 Rajendra Place, New Delhi-110008, INDIA.
+91-11-25784221 +91-7042828540 info@indianbusinessparty.org, indianbusinessparty@gmail.com
www.facebook.com/indianbusinessparty twitter.com/InBusinessParty www.linkedin.com/in/indianbusinessparty

यह सत्य है कि विश्व बिरादरी भारत सरकार पर कर सुधार हेतु एक दबाब सा बना रही है और विदेशी निवेश भी कर सुधार की अभाव में लंबित है ,पर यह भी सत्य है कि अपना देशी कारोबारी इतना सक्षम हो चला है कि वह अपने अकेले दम पर अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सके ,युवाओ को रोजगार दे सके तथा भारत को विकास शील से विकसित राष्ट्र बना सके | आज भारत का उद्यमी विदेशो में अपना परचम लहराहा है ,ऐसे में हमे विदेशी निवेश पर निर्भरता कि आवश्यकता नहीं है |

GST कौंसिल के अभी तक बैठके चल रही है , करो की दरों में रोज बदलाव लाये जा रहे है , e-forms अभी आने बाकी है , अभी तक भी 100 % कारोबारिओ का पंजीकरण भी पूरा नहीं हो पाया है | GST का सॉफ्टवेयर शायद अभी तक पूर्ण रूप से तैयार नहीं है | जब सरकार ही पूरी तरह से तैयार नहीं है तो आधे अधूरे कर ढांचे को कारोबारिओ को क्यों थोपा जा रहा है ?

ऐसा प्रतीत होता है कि कानून निर्माताओं ने GST कानून बनाते वक़्त यह धारणा मन में बैठा रखी थी की भारत का व्यापारी चोर है अतः इतना सख्त और पेचीदा कानून बनाया कि व्यापारी उसी मे उलझ कर रह गया | सरकारी अधिकारी साल में सिर्फ 200 दिन काम करके 365 दिनों का वेतन पता है जबकि व्यापारी साल में 365 दिन काम करता है और उसे कुछ लाभ होगा ,इस बात के कोई गारंटी नहीं है | GST कानूनों का पालन करने में उसे अतिरिक्त समय निकलना पड़ेगा यह सुनिश्चित है |

प्रधान मंत्री जी आपसे अनुरोध है के **GST** लागू करने की अपने निर्यण पर पुनः विचार करे और **GST** को **2019** के लोकसभा चुनाव तक स्थागित किया जाये और लोक सभा चुनाव के साथ साथ ही **GST** पर जनमत करा लिया जाय और तदानुसार निर्णय लिया जाये |

सादर

वी के बंसल
राष्ट्रीय अध्यक्ष

दिनांक :14 जून 2017

सेवा में
माननीय प्रधान मंत्री जी
भारत सरकार
नई दिल्ली